daily which can be availed of by the passengers who travel from Delhi to Calcutta ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) and (b). Indian Airlines are aware of the need for a direct service between Calcutta on the one hand and Agartala on the other, providing a connection to Delhi on the same day. The Corporation therefore, plans to provide such a service from 15.10.1971, as part of its winter schedule.

SHRI DASARATHA DEB : Will the service have connection from Gauhati to Agartala and Calcutta to Agartala ?

DR. KARAN SINGH : Yes.

अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये गैर-सरकारी बोर्ड की स्थापना

*1499. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवती समिति ने अन्तर्देशीय जल परिवहन को सक्रिय बनाने की दृष्टि से अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए एक गैर सरकारी बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है और बोर्ड की स्थापना में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) : (a) Yes, Sir,

(b) The recommendation of the Committee is under consideration and a decision will be taken after examining the proposal from all aspects as early as possible.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या यह सही है कि बोर्ड बनाने में इस लिए देरी हो रही कि आप के अधिकारी चाहते हैं कि आफिशियल बोर्ड बने ?

श्री ओम मेहता : यह सरकारी बोर्ड बन रहा है, इसमें गैर सरकारी मेम्बर्ज भी लिए जायेंगे ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : मन्त्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि "एज-अर्ली-एज-पासिबल" —यह बड़ी वेगटर्म है । क्या यह सही है कि आपके अधिकारी किसी आफिशियल बोर्ड को बनाना चाहते हैं, इस लिए गैर-सरकारी बोर्ड बनने में देरी हो रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : ऐसी बात नहीं है । अगर गैर-सरकारी बोर्ड की आवश्यकता होगी अथवा बोर्ड पर गैर-सरकारी व्यक्तियों की नामजदगी की आवश्यकता होगी तो उसके बारे में जो कुछ भी होगा, उचित विचार किया जायेगा ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : माननीय मन्त्री जी ट्रांसपोर्ट और शिपिंग के मन्त्री हैं —पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे—उनको स्मरण होगा कि 1957 में एक गोखले कमेटी बनी थी, उसने 1959 में रिपोर्ट दी, उसके बाद एक आफिशियल बोर्ड बना, जिसकी केवल एक मीटिंग हुई और 9 वर्ष तक कोई प्रगति नहीं हुई, उसकी रिकमेन्डेशन्ज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई । उसके बाद 1968 में भगवती कमेटी बनी, उसकी रिकमेन्डेशन्ज भी आ चुकी हैं । आफिशियल बोर्ड के रिजल्ट को देखा जा चुका है, इस लिए नान-आफिशियल बोर्ड ही इस बारे में काम कर सकेगा । क्या सरकार इसके लिए कोई डेट तय करेगी ?

श्री ओम मेहता : जहां तक आफिशियल —नान-आफिशियल बोर्ड का सवाल है—एक

बोर्ड जल्द बनेगा, उसमें नान-प्राफिशयल लोगों को भी लिया जायेगा ।

श्री सरजू पांडे : भगवती साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने किन-किन स्थानों पर नौका-परिवहन चलाने की सिफारिश की थी ? क्या उसमें गाजीपुर में नौका चलाने की बात कही गई थी ?

श्री राज बहादुर : पटना से गाजीपुर तक नदी सेवा चलाने पर विचार किया जा रहा है ।

Revision in the Pay Scales of Primary School Teachers

*1500. SHRI A. N. CHAWLA : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether a group of Primary School teachers staged a 48 hour dharna in front of the Ministry of Education to Press their demands for higher emoluments ;

(b) whether the issue of increase in salary of Primary School teachers has been hanging on for quite a long time ; and

(c) the stage at which the proposal to revise the salaries of Primary School teachers stands at present and the time likely to be taken in taking a final decision in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAVA) : (a) A dharna was staged by a few persons on 12th July, 1971, for 48 hours in front of Shastri Bhawan.

(b) and (c). The question of further revision of pay scales of Delhi teachers including primary schools teachers, is already under the consideration of Government of India and a decision in the matter will be taken as soon as possible.

SHRI A. N. CHAWLA : May I know from the hon. Minister whether the revision of scales last year had widened the gap between the salaries of the principals and those of the teachers and, if so, by what amount ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : There is some substance in the contention that as a result of the revision, the percentage increase given to the principals was more than the percentage increase given to the teachers. That is what really the Government is now concerned with : that before considering any revision no anomaly should crop up. It is further complicated by the fact that the whole thing is before the Pay Commission. It is under active consideration of the Government.

SHRI A. N. CHAWLA : May I know from the hon Minister whether the difference between the pay of Delhi teachers and the pay of those in the neighbouring States will also be removed ?

SHRI H. R. GOKHALE : When the scales are fixed, naturally an attempt will be made to rationalise the pay-structure.

श्री राम सहाय पांडे : स्कूल अध्यापकों की स्थिति बड़ी शोचनीय है और सबसे पहले वे आते हैं जो पटिया पुजाते हैं । विद्या अध्ययन का प्रारम्भ उन्हीं से होता हैं । क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाना चाहती है, जिससे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश कोई अन्तर न हो, उचित वेतन वृद्धि हो जिसमें उनका जीवन-यापन हो सके ? क्या आप कोई ऐसी नीति या परम्परा बनाना चाहते हैं जिसमें उनका सन्तोष हो सके और उनको अच्छा वेतन मिल सके ?

SHRI H. R. GOKHALE : Primarily it is a question for the State Governments to consider. When this will be considered by the Central Government, an attempt will be made to rationalise the pay-structure.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह राज्य सरकारों का मामला है, लेकिन दिल्ली तो केन्द्र प्रशासित है । मैं जानना चहता हूं कि अभी प्राइमरी शिक्षकों का वेतनमान क्या है और वे कितना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ?